नई सोच, नया आयाम

RNI No. CHHHIN/2009/35020

जोहार छत्तीसगढ़

दैनिक हिन्दी

◆ वर्ष: -14 ◆ अंक: 252 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 ◆ मूल्य: 2 ₹ ◆ पृष्ठ : 4

धरमजयगढ़, गुरुवार 21 जुलाई 2022

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

पेज -3 पर सोरिद में 75 लाख की लागत से बनेगा हाईस्कूल भवन

कोरोना से उठा पिता का साया तो मिला अनुकम्पा नियुक्ति का सहारा पेज -4 पर

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र

सिंहदेव के इस्तीफे पर विपक्ष का हंगामा, बताया संवैधानिक संकट, कार्यवाही स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। शून्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफे के मुद्दे पर हंगामा हो गया। पूर्व योजना के मुताबिक विपक्ष ने इसपर सवाल उठाए। इसको व्यवस्था का प्रश्न बताकर सरकार से जवाब मांगा गया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को पहले 10 मिनट के लिए और बाद में गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

शून्यकाल शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

उन्होंने कहा, प्रदेश में संविधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मंत्री ने पत्र लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामूहिक उत्तरादायित्व के तहत उन आरोपों पर मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों का जवाब आना चाहिए। भाजपा के दूसरे विधायकों ने इस पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, एक मंत्री का मुख्यमंत्री को पत्र लिखना संविधानिक संकट और व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने की भी विधानसभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं है। भाजपा विधायकों ने कहा, मंत्रियों के तय प्रोटोकाल का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना काल में फैसलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अभी भी फैसले ले रही है। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को 10मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

दिवंगत नेताओं को सदन ने दी श्रद्धांजलि

सदन ने दिवंगत पूर्व सांसद चक्रधारी सिंह और पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 10 मिनट बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसमें वन विभाग, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन और खनिज विभाग से सवाल पूछे जा रहे हैं।

प्रोक्सी या एवजी शिक्षकों के विरुद्ध तत्काल एक्शन के निर्देश

रायपुर। सुदूर अंचलों में स्थित शालाओं में निरीक्षण के दौरान प्रोक्सी मतलब अपने स्थान पर एवजी शिक्षकों के कार्यरत होने की जानकारी प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही प्रोक्सी अथवा एवजी शिक्षकों की जानकारी प्राप्त होने पर संकुल समन्वयकों के माध्यम से तत्काल इसकी शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को करवाते हुए एक्शन लेने कहा गया है। एवजी या प्रोक्सी शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए आगामी दस दिनों के भीतर सभी शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के फोटो और उनके नाम

सभी शासकीय शिक्षकों की विवरण सहित फोटो शाला परिसर की बाहरी दीवार में होगी प्रदर्शित

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

सहित विवरण बाहरी दीवार पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासकीय शिक्षकों के दस्तावेजों का कार्यालय में वेरिफिकेशन करते हुए प्रमाणीकरण करने कहा गया है। शाला प्रबन्धन समिति के साथ सभी कार्यरत शासकीय शिक्षकों का परिचय सत्र आयोजित कर प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके समक्ष शाला गुणवत्ता सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रस्तुतीकरण करने भी कहा गया है।

एक नजर

मौसम विभाग ने दी चेतावनी:बिलासपुर संभाग सहित 20 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट

रायपुर । छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. बलरामपुर-रामानुजगंज को छोड़ दें तो लगभग हर जिले में औसत से अधिक ही वर्षा हो रही है. दक्षिण बस्तर में तो ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है। नदी-नाले उफान पर हैं. इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, महासमुंद समेत करीब 20 जिलों में बुधवार को बारिश के साथ ही आंधी तूफान चलने के आसार हैं. इसको लेकर लोगों को सावधान रहने कहा गया है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन 20 जिलों में आंधी तूफान के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. दक्षिण बस्तर में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ के मध्य इलाके दुर्ग, रायपुर, बालोद, राजनांदगांव में हल्की बारिश हो सकती है. सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है. बारिश को लेकर लोगों को अलर्ट भी किया गया है. रायपुर मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक आगामी चार से पांच दिन तक लगभग यही स्थिति बनी रहेगी।

बस्तर की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की थीम पर आधारित है मुख्यमंत्री का विधानसभा कार्यालय कक्ष

लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है सौंदर्यीकरण कार्य

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है सौंदर्यीकरण कार्यमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। कार्यालय कक्ष का प्रवेश द्वार गांव के किसी घर के प्रवेश द्वार का अहसास दिलाता है। कार्यालय कक्ष के प्रवेश पर बस्तर के परंपरागत आदिवासी नृत्यों को उकेरा गया है जिससे बस्तर की संस्कृति का सजीव अहसास होता है। बस्तर आर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज पर आधारित कलाकृतियां

भी उकेरी गयी हैं।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार, विधायक श्री मोहन मरकाम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।

स्कूलों में टीचर्स के फोटो क्योंकि दूसरे कर रहे ड्यूटी

छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में फर्जीवाड़ा,शिक्षक अपनी जगह किसी और को भेज रहे पढ़ाने

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में एवजी या प्रॉक्सी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यानी वहां नियुक्त शिक्षकों ने स्कूल जाने के लिए अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को तैनात कर दिया है।

इस महीने स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू हुआ तो अफसरों के सामने इस फर्जीवाड़े की पोल खुली है। यह जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग स्कूलों में तैनात शिक्षकों की फोटो वहां की दीवारों पर लगाने जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेन्द्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अगले 10 दिनों में इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रॉक्सी अथवा एवजी शिक्षकों की जानकारी प्राप्त होने पर संकुल समन्वयकों के माध्यम से तत्काल इसकी शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को करवाते हुए एक्शन लेने को भी कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है, एवजी या प्रॉक्सी शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए सभी स्कूलों में कार्यरत सरकारी शिक्षकों के फोटो, उनके नाम और जरूरी विवरण सहित स्कूल की बाहरी दीवार पर प्रदर्शित की जाए। सरकारी शिक्षकों के दस्तावेजों का कार्यालय में वेरिफिकेशन करते हुए प्रमाणीकरण करने भी कहा गया है। शाला प्रबंधन समिति के साथ सभी कार्यरत सरकारी शिक्षकों का परिचय सत्र आयोजित कर प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके समक्ष शाला गुणवत्ता सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रस्तुतीकरण करने भी कहा गया है।

छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई को हरेली से होगी गौ-मूत्र खरीदी की शुरूआत- मुख्यमंत्री

रायपुर। गोबर खरीदी के एवज में अब तक पशुपालकों, ग्रामीणों को 153.44 करोड़ रूपए का भुगतानमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 28 जुलाई को हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ-साथ गौ-मूत्र की खरीदी की शुरूआत की जाएगी।

गौ-मूत्र की खरीदी के लिए 4 रुपए प्रति लीटर की दर प्रस्तावित की गई है। खरीदे गए गौ-मूत्र का

उपयोग जीवामृत कीटनाशकों और खाद के निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे राज्य में जैविक खेती को और मजबूती मिलेगी तथा पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में 'गोधन न्याय योजना' की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 48वीं किश्त की राशि के रूप में 7 करोड़ 48 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय पर बोनस दिया जाएगा।

अब तक 50 फीसदी से ज्यादा में बोनी

महासमुंद । अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। कृषि विभाग द्वारा अब तक 68,016 कृषकों को खेती किसानी के लिए 299 करोड़ 92 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2021-22 खरीफ वर्ष में 54,082 कृषकों को खेती-किसानी के लिए 220.93 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था। सहायक संचालक कृषि अमित मोहंती ने बताया कि किसानों ने खरीफ वर्ष 2022-23 में लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा बोनी पूरी कर ली है। किसान धान रोपा में व्यस्त हो गए हैं। हर तरफ खेतों में महिलायें रोपा लगाती हुई नजर आ रही है। कृषि विभाग द्वारा जिले में तकरीबन 264.200 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल बोनी का लक्ष्य है, जो पिछले खरीफ वर्ष से ज्यादा है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का किया लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री पेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार, विधायक मोहन मरकाम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधानसभा बृजमोहन के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने सदन में दी जानकारी वित्त ने दी 35981 पदों पर भर्ती की स्वीकृति

लाखों नौकरियों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार 20 हजार लोगों को भी नहीं दे पाई नौकरी - बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का मामला विधानसभा में उठाते हुए मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि 1 जनवरी 2019 से 26 जून 2022 तक वित्त विभाग ने किन-किन वर्ग के कितने कितने पदों की भर्ती की सहमति / स्वीकृति दी है और उसमें कितने कितने पदों की भर्ती हो गई है ? क्या 3 जनवरी 2022 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर ,स्टेनो टाइपिस्ट, और

डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक आहर्ता में नई आहर्ता जोड़ी गई है ? यदि हां तो क्या और क्यों जोड़ी गई जोड़ी गई ? अहर्ता के लिए 26 जून 2022 तक कब कब परीक्षा आयोजित हुई है ? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है ? पदों पर भर्ती के लिए मंत्रालय व्यापम से भर्तियां हो रही है उसमे अभ्यर्थियों के चयन के बाद क्या कंप्यूटर कौशल परीक्षा ली जाती है ?

मुख्यमंत्री भूपेश ने अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रदेश में साढ़े 3 सालों में सिर्फ 18199 बेरोजगारों को नौकरी दी है । वित्त विभाग ने साढ़े 3 सालों में सिर्फ 35981 पदों की स्वीकृति जारी की है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर में यह भी बताया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर , स्टेनो टाइपिस्ट, वह सहायक ग्रेड 3 के परीक्षा में मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिंदी दो अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में पास का प्रमाण पत्र जोड़ा गया है । वही यह भी स्वीकार कर रहे है कि जोड़ी गई आहर्ता के लिए 26 जून 2022 तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। शीघ्र परीक्षा आयोजित करने के लिए संचालक लोक शिक्षण संचनालय को निर्देशित किया गया है ।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि जब परीक्षा की आयोजित नहीं हुई है तो फिर इसमें प्रमाण पत्र धारी बेरोजगार मिलेंगे कहां से और जब प्रमाण पत्र नहीं है तो भर्ती कैसे होगी ? श्री अग्रवाल ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है दूसरी तरफ विधानसभा में अपने प्रश्न के उत्तर में वही बता रहे हैं कि प्रदेश में अब तक 18199 लोगों को ही नौकरी दी गई है।

नारायणपुर जिले के विशेष पिछड़ी अबुझमाड़िया जनजाति के 7 युवाओं को मिला शासकीय नौकरी का नियुक्ति पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति जताया आभारनारायणपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया के सात युवाओं को शासकीय नौकरी प्रदान की गई है। उन्हें आज कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन सात युवाओं सहित 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के साथ शासकीय नौकरी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इसी मंशानुरूप सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए

विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता देने के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति जताया आभार

विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक उत्थान के लिए इस वर्ग के पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग में शासकीय नौकरी में प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थी लगन के साथ काम करें। स्थानीय स्तर पर ही शासकीय नौकरी मिलने से विशेष पिछड़ी अबुझमाड़िया जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों में उत्साह देखा जा रहा है।

आदिवासियों के प्रति नजरिया बदलें, आया सालों से पैठ बन चुकी सामाजिक दूरियां का मिटाने का वक्त

सोमवार को हुए मतदान के बाद राजग के संख्याबल को देखते हुए आदिवासी नेत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। इससे एक उम्मीद बंधती है कि 15वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद देश की आदिवासी आबादी की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में चर्चा जोर पकड़ेगी। देश की आदिवासी आबादी के बारे में सामान्य रूढ़ियों से अलग हटकर सोचे जाने की तत्काल आवश्यकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में आदिवासियों की आबादी कुल आबादी का करीब 8.6 फीसदी यानी 10.4 करोड़ थी। पिछले वर्ष दिसंबर में प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक आधिकारिक बयान में आदिवासी आबादी (एसटी) के बीच प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया था। जैसे, बयान में कहा गया था कि वर्ष 2001 में आदिवासियों की साक्षरता दर 47.1 फीसदी थी, जो 2011 में बढ़कर 59 फीसदी हो गई। इसके अलावा, समय-समय पर होने वाले श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट (जुलाई 2019-जून 2020) में बताया गया है कि एसटी की साक्षरता दर बढ़कर 70.1 फीसदी हो गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) प्लस रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर एसटी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2012-13 में 62.4 फीसदी था, जो 2019-20 में बढ़कर 76.7 फीसदी हो गया है। ये सभी अच्छी खबरें हैं। लेकिन विभिन्न मोर्चों पर प्रगति के बावजूद देश की आदिवासी आबादी कई क्षेत्रों में पीछे है और उनके लिए वैधानिक आरक्षणों के अलावा और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के समर्थन से मानव विकास संस्थान (आईएचडी) द्वारा लाई गई एक नई रिपोर्ट- %अनुसूचित जनजाति मानव विकास रिपोर्ट 2022% बताती है कि एसटी समुदाय स्वास्थ्य एवं पोषण के अधिकांश संकेतकों पर अन्य सामाजिक समूहों से पीछे है। हालांकि एसटी में बच्चों के बचने की दर में सुधार हुआ है, लेकिन पांच साल से कम उम्र के आदिवासी बच्चों की मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा है।

राष्ट्रपति चुनाव

कई आदिवासी समुदाय दुर्गम ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, लेकिन दूरी और दुर्गमता के कारण इन्हें बुनियादी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों की रूढ़िवादी छवि को भी तोड़ने की तत्काल आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। एक तरफ जहां अनुसूचित जनजाति आबादी और अन्य समुदायों के बीच बुनियादी सामाजिक सेवाओं, विशेष रूप से बिजली, पीने के पानी की सुविधा, आवास, स्कूल में उपस्थिति, 18 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु, पोषण और टीवी व मोबाइल फोन का स्वामित्व-तक पहुंच में असमानताओं की खाई कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा, कंप्यूटर कौशल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कंप्यूटरों तक पहुंच जैसी नई या उन्नत क्षमताओं व सुविधाओं के मामले में दरार बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़े इन महत्वपूर्ण अंतरालों पर भी ध्यान देते हैं, जो आदिवासी समुदायों के विकास को पटरी से उतारते हैं। स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं की बात करें, तो जिन घरों में साफ-सफाई की उचित सुविधा नहीं है, उनमें डायरिया, पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा अच्छी स्वच्छता सुविधाओं वाले परिवारों की तुलना में अधिक होता है। लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019-2021) के अनुसार, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्य में मात्र 66 फीसदी अनुसूचित जनजाति के परिवारों में ही शौचालय की सुविधा है, जबकि जो परिवार आदिवासियों, दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के नहीं हैं, उनके 92 फीसदी घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। यह मुझे अपनी उस रिपोर्ट की याद दिलाता है, जो मैंने 2007 में लिखी थी।

उस वर्ष ओडिशा के तीन आदिवासी बहुल जिले-कोरापुट, रायगडा और कालाहांडी हैजा के प्रकोप के कारण चर्चा में थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन तीन जिलों में हैजा और हैजा जैसी अन्य बीमारियों से 155 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रभावित जिलों में आदिवासियों के बीच काम करने वाले एक एनजीओ से मैंने बात की, तो उसके एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों की कमी और स्थानीय स्वास्थ्य तंत्र के कमजोर ढांचे के कारण मृत्यु में इजाफा हुआ। इन आदिवासी इलाकों में कर्मचारियों की कमी के कारण आपात स्थिति से निपटने के लिए दूसरे जिलों से डॉक्टरों की कई टीम बुलानी पड़ी थीं। कई आदिवासी समुदाय दुर्गम ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, लेकिन दूरी और दुर्गमता के कारण इन्हें बुनियादी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों की रूढ़िवादी छवि को भी तोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। इस साल मार्च में आदिवासी इलाकों में जनजातीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के मूल्यांकन पर बात करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने सहानुभूति की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी समाजों के स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है, तो हम अक्सर मान लेते हैं कि वे अंधविश्वासी हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। जब स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उनके पास नहीं पहुंचती हैं, तो वे विकल्प तलाशते हैं। वे निश्चित तौर पर आधुनिक देखभाल सेवाएं स्वीकार करते हैं।

पत्रलेखा चटर्जी

संपादकीय

लोकप्रिय है अग्निपथ योजना?

2022 के बैच के लिए रिकॉर्ड 7,49,899 आवेदन उसे मिले हैं। सरकारी पक्ष ने इसे इस योजना की लोकप्रियता का सबूत माना है। लेकिन क्या यह सच है? अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए भारतीय वायु सेना ने अग्निवीरों की आर्जियां आमांत्रित कीं। 2022 के बैच के लिए रिकॉर्ड 7,49,899 आवेदन उसे मिले हैं। सरकारी पक्ष ने इसे इस योजना की लोकप्रियता का सबूत माना है। लेकिन क्या यह सच है? हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आईं, जिनमें बताया गया कि कहीं चपरासी तो कहीं सफाई कर्मी के पद के लिए लाखों अर्जियां आ गईं? तो क्या यह माना जाएगा कि उन पदों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? अथवा, यह देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी का सबूत है, जिसमें नौजवान कोई भी काम किसी भी शर्त पर करने को बेताब हैं? भारतीय वायु सेना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पांच जुलाई को पूरी हुई। वायु सेना ने अपने ट्वीट में बताया है कि उसे अग्निवीर योजना में कुल 7,49,899 आवेदन मिले, जो कि इससे पहले तक किसी भी भर्ती चक्र में अधिकतम आवेदन 6,31,528 की तुलना में कहीं अधिक है। वायुसेना में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अब सभी आवेदकों को चयन परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। वायुसेना अग्निवीर-वायु कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा 25 जुलाई से आयोजित होने वाली है। चुने गए गए उम्मीदवारों को एक दिसंबर को पीएसएल राउंड के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन की घोषणा 11 दिसंबर को होगा। वायु सेना 2022 के लिए 3,500 अग्निवीरवायु की भर्ती करेगी।

बत्तीस साल बाद न्याय की उम्मीद, मानो समय ने एक चक्र पूरा कर लिया

न्याय की परिधि में मानो समय ने एक चक्र पूरा कर लिया है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि 32 वर्ष पहले कश्मीर में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद अपहरण का मामला फिर से खुलेगा और न्यायिक प्रक्रिया मुकाम पर पहुंचने की ओर अग्रसर होगी? पिछले 16 जुलाई को जम्मू के टाडा न्यायालय में रुबिया सईद ने यासीन मलिक समेत चारों आरोपियों की पहचान की। यासीन मलिक आतंक के वित्तपोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कैद की सजा भुगत रहा है।

दरअसल जिस दिन मोदी सरकार ने अलगाववादी नेताओं तथा पूर्व आतंकवादी से नेता बने लोगों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां निवारक कानून के तहत मामला दर्ज किया, उसी दिन साफ हो गया था कि कश्मीर में 90 के दशक में हुए भयावह अन्याय के न्यायिक प्रतिकार का रास्ता बन चुका है। आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार लोगों को सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। इसी के तहत यासीन मलिक से जुड़े मामले भी पुलिस और एनआईए ने खोल दिए। रुबिया सईद अपहरण तब सर्वाधिक चर्चित मामला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर ही कई हलकों में आरोप लगा था कि उन्होंने जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अपनी बेटी के अपहरण का नाटक रचवाया था। श्रीनगर के सदर पुलिस थाने में आठ दिसंबर,

प्रक्रिया

पहली बार मोदी सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा से संबंधित वारदातों को सही परिप्रेक्ष्य के साथ कानून के कठघरे तक लाने का साहस किया है। इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई कि रुबिया सामान्य तरीके से न्यायालय पहुंचीं और उन्होंने गवाही दी वह आगे जिरह में भी उपस्थित रहने को तैयार हैं।

1989 को रुबिया सईद अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इसके अनुसार, रुबिया ट्रांजिट वैन से श्रीनगर के ललदेद अस्पताल से नौगांव अपने घर जा रही थी। तब वह एमबीबीएस करने के बाद अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। वैन जब चांदपुरा चौक के पास पहुंची, तो उसी में सवार तीन लोगों ने बंदूक के दम पर वैन रोककर रुबिया का अपहरण कर लिया। बाद में उन्होंने अपने साथी आतंकियों को जेल से छोड़ने की मांग की। इस मामले में यासीन मलिक, मेहराजुद्दीन शेख, मोहम्मद जमाल, अमीर मंजूर अहमद सोफी के अलावा अली मोहम्मद अमीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफी, वजाहत बशीर और शौकत अहमद बख्शी के नाम शामिल हैं।

गृहमंत्री की बेटी का अपहरण असाधारण घटना थी। पूरा देश सकते में था। अंततः सरकार ने 13 दिसंबर को पांच आतंकवादियों को रिहा किया, जिसके बाद रुबिया को छोड़ा गया। छोड़े गए आतंकवादियों में शेर खान पाक अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दूसरा भी सुरक्षा बलों द्वारा श्रीनगर में मारा गया।

जावेद जरगर और नूर मोहम्मद याहिन जेल में हैं। हां, अल्ताफ अहमद बेंगलूरू में रेस्त्रां चला रहा है। न्यायालय ने 29 जनवरी, 2021 को रुबिया सईद अपहरण मामले में यासीन मलिक व अन्य को आरोपी करार दे दिया। रुबिया सईद अपहरण मामले का खुलना केवल एक अपहरण की न्यायिक प्रक्रिया भर नहीं है।

यह जम्मू और कश्मीर में आए व्यापक बदलाव का प्रमाण है। रुबिया सईद अपहरण कांड जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उससे आतंकवादियों का हौसला बढ़ा और उन्होंने जो कहर बरपाया, वह इतिहास का भयानक अध्याय बन चुका है। वीपी सिंह के बाद आई नरसिंह राव की सरकार ने भी रुबिया अपहरण मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई। हालांकि उस दौरान आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई हुई एवं जम्मू और कश्मीर में इतनी शांति स्थापित हुई, कि 1996 में विधानसभा चुनाव कराया जा सका।

अवधेश कुमार

मिला जुला

कलेक्टर बने स्टूडेंट, 11 वीं के विकास ने पढ़ाया समकोण त्रिभुज का गणित

शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल नगर और नगर से रटगा सड़क निर्माण का औचक निरीक्षण

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने एसपी त्रिलोक बंसल के साथ बैकुंठपुर विकासखण्ड के विभिन्न स्थलों का दौरा किया। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर ने बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज तैयार करने चिन्हांकित भूमि का निरीक्षण किया और एसडीएम बैकुंठपुर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। शासन के निर्देश अनुसार नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज तैयार किये जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदंब जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज के लिए चिन्हित स्थल पर वृक्षों का रोपण प्रारंभ किया जाएगा।

शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल नगर और नगर से रटगा सड़क निर्माण का औचक निरीक्षण

कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल नगर का औचक निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की। इस दौरान उन्होंने कक्षा 11 वीं के कृषि संकाय के बच्चों से बात कर पढ़ाई पर चर्चा की। कलेक्टर स्वयं छात्र-छात्राओं के साथ बैठे और बच्चों ने समकोण त्रिभुज का गणित पढ़ाया। कलेक्टर ने बच्चों से अच्छे से पढ़ाई करने प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद कलेक्टर शर्मा ने नगर तिहाई पारा से रटंगा टेमरापारा 2.3 किमी सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंए समय वृद्धि नही दी जाएगी और लापरवाही पर पेनल्टी की कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान एसडीएम बैकुंठपुर एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कृष्ण कुंज के लिए चिन्हांकित भूमि का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रोक्सी या एवजी शिक्षकों के विरूद्ध तत्काल एक्शन के निर्देश

सभी शासकीय शिक्षकों की विवरण सहित फोटो शाला परिसर की बाहरी दीवार में होगी प्रदर्शित

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

सुदूर अंचलों में स्थित शालाओं में निरीक्षण के दौरान प्रोक्सी मतलब अपने स्थान पर एवजी शिक्षकों के कार्यरत होने की जानकारी प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेन्द्र दुग्गा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही प्रोक्सी अथवा एवजी शिक्षकों की जानकारी प्राप्त होने पर संकुल समन्वयकों के माध्यम से तत्काल इसकी शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को करवाते हुए एक्शन लेने कहा गया है। एवजी या प्रोक्सी शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए आगामी दस दिनों के भीतर सभी शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के फोटो और उनके नाम सहित विवरण बाहरी दीवार पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासकीय शिक्षकों के दस्तावेजों का कार्यालय में वेरिफिकेशन करते हुए प्रमाणीकरण करने कहा गया है। शाला प्रबन्धन समिति के साथ सभी कार्यरत शासकीय शिक्षकों का परिचय सत्र आयोजित कर प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके समक्ष शाला गुणवत्ता सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रस्तुतीकरण करने भी कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी शालाओं में आगामी दस दिनों के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है। जिससे राज्य स्तर से निरीक्षण के दौरान सभी शालाओं में यह व्यवस्था लागू होने की सूचना मिल सके।

चेकिंग के दौरान ले ली जान

हरियाणा के बाद झारखंड में महिला पुलिस अधिकारी को वैन ने कुचला

रांची। हरियाणा के बाद अब झारखंड के रांची जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला दरोगा की पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला पुलिस अधिकारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, वाहन चालक वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में सफल रहा. पुलिस का दावा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह मामला रांची जिले के तुपुदाना इलाके का है. जहां बुधवार तड़के 3 बजे 2018 बैच की पुलिस एसआई संध्या टोपनो वाहनों की चेकिंग कर रही थीं. इसी दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने एक पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया था. लेकिन ड्राइवर ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर महिला दरोगा को रौंद दिया. इस घटना में महिला पुलिस अधिकारी की घटनास्थनल पर ही मौत हो गई. वहीं, आरोपी पिकअप वैन का चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहा. घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दरोगा के शव को कब्जे में लिया. इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. पुलिस ने इस मामले के एक आरोपी की गिरफ्तारी और वाहन की बरामदगी की पुष्टि की है।

हरियाणा में DSP को कुचला

उधर, बीते दिन यानी मंगलवार दोपहर ही हरियाणा के नूंह जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने गए एक पुलिस उपाधीक्षक (ष्टस्क्क) को डंपर से कुचलकर मार डाला गया. तावडू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने दस्तावेज की जांच के लिए एक डंपर को रुकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें कुचल डाला. पुलिस ने बताया कि घायल अधिकारी को फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

बीमारियों से बचाव के लिए घर घर जाकर किया जा रहा स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

जिले के कोंटा नगर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ के कारण लगभग सभी रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति रही। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही, सड़कों से मलबा हटाकर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए घर घर घूमकर वार्ड वासियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाईयां प्रदान की जा रही है। वहीं मच्छरों से बचाव के लिए वार्डों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासन द्वारा मच्छरदानी भी

उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए हैंडपंप, बोरवेल एवं अन्य जल स्त्रोतों में क्लोरिनेशन का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

20 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि उद्योग के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तथा व्यवसाय के लिए 2 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर शासन द्वारा 10 से 35 प्रतिशत तक अनुदान नियमानुसार दी जाएगी। योजना का लाभ न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण जिले के स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को पासपोर्ट साईज फ टो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भूमि का नक्शा खसरा, नगरीय निकाय क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सुकमा कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक.38 में आवेदन कर सकते है।

आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

आम जनता के लिए जिंदगी का गुजारा करना काफी मुश्किल होते जा रहा है। गरीब तबका तो पहले से ही परेशान हैं। लेकिन अब तो मध्यवर्गीय परिवार को भी अपनी आए और वय और मे सामंजस्य बैठाना बेहद मुश्किल हो रहा है।

करोना काल के बाद आम आदमी मंदी व सभी क्षेत्रों में बढ़ती महंगाई ने आम जनता को जीवन यापन एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं व पेट भरने वाली रसोई के बढ़ते बजट में आम व खास सभी वर्ग के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगाकर महंगाई की मार ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में आम जनता के लिए जिंदगी का गुजारा काफी मुश्किल होता जा रहा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ रही। बाजार पर दिख रही है। और रसोई गैस के किचन का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। बढ़ती महंगाई ने लोगों को आवश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए विवश कर दिया है। बाजार कारोबारियों के प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाज व खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही साबुन, शैंपू,बिस्किट, की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बजट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह है। कि खाद्य तेलो की कीमतें में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। इनकी कीमतें 40 फीसदी से अधिक बढ़ गई। है एसपी से एक 50 रिटर्न बिकने वाला होली पर 200 प्रति लीटर में बिक रहा है इसी प्रकार 130 से 150 रुपए लीटर मे बिकने वाला खाद्य तेल अब 200 लीटर हो गया है । वही 350 रुपए किलो में बिकने वाली चाय किलो अभी 510 किलो पहुंच गई है सोया तेल 111 फीसदी आटा 7 फीसदी और अरहर की दाल 45 फ़ीसदी महंगाई हो गई है। बीते 10 माह के दौरान दूध की कीमत दो बार बढ़ चुकी है। हेयर आयल की कीमत 280 से बढ़कर 340 हो गई है। महंगाई को लेकर राजनीतिक भी अपने चरम पर है। केंद्र सरकार की अपनी दलीलें है। और उस वक्त भी अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से विरोध और आलोचना कर रहा है ।लेकिन इन सबके बीच आम आदमी को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं देती सरकार बदलती गई है। लेकिन महंगाई नहीं रुकी महंगाई घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। आम आदमी के लिए परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो बड़े लोगों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता परंतु उन गरीब लोगों का क्या जो किसी प्रकार से दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। बढ़ती महंगाई ने आम जनता बेहद परेशान है। आए दिन किसी ना किसी चीज के भाव बढ़ने की खबर आती रहती है। मगर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

आमदनी अठन्नी,खर्चा रुपैया

आम लोगों के लिए लगातार बढ़ती महंगाई से हाहाकार मच रहा है। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। बढ़ती महंगाई ने लोगों का घरेलू बजट तहस-नहस करके रख दिया है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। खाद्यान्न तेल किराना सामान और दूध के दाम में वृद्धि से लोगों के भोजन की थाली महंगी होती जा रही है। हरी सब्जियों और फलों के दाम में भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। हरी सब्जियों के अभाव में टमाटर की चटनी खा पाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई पर रोक लगाने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है ।वही यह संभावना भी जताई जा रही है। कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा रुलाएगी राज्य सरकारों को इस पर लगने वाले वैट की दरों को कम करना चाहिए । ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इसके साथ ही जमाखोरी, और मुनाफ ाखोरी करने वालों के खिलाफ भी छापामारी, करवाई की जानी चाहिए। जो लंबी ऐसे से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर बाजार में संकट पैदा करते हैं। और भारी मुनाफा कमाते हैं।

एक नजर

बारिश से हुआ शहर तरबदर, घरों में घुसा पानी, जलमग्न हुए खेत

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

मूसलाधार वर्षा से क्षेत्र जल थल हो गया तेज वर्षा के कारण पूरे गांव में कहीं पानी भर जाने से जीवन अस्त.व्यस्त हो गया हालत यह रहा कि जिन स्थानों पर कभी बरसात का पानी नहीं भरता था। वहां भी कई कई जगह पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा घरों में भी बरसात का पानी घुस जाने से लोग परेशान हुए लोग को बाल्टी ओ सारे पानी को बाहर निकालना पड़ा गली मोहल्ले में पानी भरने से लोग घरों में ही दुबके रहे नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास रहने वाले लोगों मे भय हैं ।वहीं क्षेत्र में कच्ची मिट्टी के मकानों में रहने वाले वर्षा रुकने का इंतजार कर रहे थे नजारा है। जिससे फर्शी खदानों में पानी भर जाने से मजदूरों को काम करते नहीं बन रहा है। क्षेत्र के कई गांव में गली से लेकर घरों में घुसे वर्षा का पानी जिसको निकलने के लिए ग्रामीण दिनभर मशक्कत करते रहे। लगातार हो रही बारिश से खेतों में धान के पौधे भी प्रभावित हुए। अधिकांश खेत लबालब तालाब में तब्दील हो गए हैं। घरों और गलियों में लगातार पानी का बहाव चल रहा है। सर जी बाड़ी में अधिक पानी गिरने के कारण काम करते नहीं बन रहा है। शहर सड़क गांव के खेत पर 3 फुट पानी भरा हुआ है।

सोरिद में 75 लाख की लागत से बनेगा हाईस्कूल भवन

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

ग्राम सोरिद में 75 लाख 23 हजार रूपए की लागत से हाईस्कूल भवन का निर्माण होगा। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की पहल पर राज्य शासन से भवन निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। भवन निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति पर ग्रामीणों ने संसदीय सचिव चंद्राकर का आभार जताया है। गौरतलब है कि संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर के प्रयास से ग्राम सोरिद में हाईस्कूल भवन के लिए बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया था। बाद इसके हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए राज्य शासन से 75 लाख 23 हजार रूपए की स्वीकृति मिली है। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर का सरपंच सेवती बाई ध्रुव, ईश्वर ध्रुव, प्रहलाद ध्रुव, देवेंद्र चंद्राकर, राजेश चंद्राकर, सियाराम विश्वकर्मा, दुष्यंत चंद्राकर, पुरूषोत्तम साहू, दशरीबाई विश्वकर्मा, मनटोरा ध्रुव घुरवाबाई यादवए नर्मदा चंद्राकर आदि ने आभार जताया है।

हरेली से होगी गौ-मूत्र की खरीदी

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

गौ पालकों को गोबर के साथ अब गौ-मूत्र भी आय का जरिया होगा। हरेली पर्व 28 जुलाई से महासमुंद जिले की दो स्वावलंबी गौठानों बिरकोनी और गोड़बहाल से इसकी शुरूआत होगी। पहले गौमूत्र खरीदी के लिए बिरकोनी के साथ बड़गांव गौठान को चिन्हांकित किया गया था। आज उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि अब गौमूत्र की खरीदी बड़गांव गौठान की जगह गोड़बहाल गौठान में होगी। दोनों गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की सभी जरूरी तैयारी अंतिम दौर में है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौमूत्र क्रय संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौठानों में गौमूत्र उसी पंचायत के पशुपालकों से क्रय किया जाएगा। इस हेतु गौठान समिति द्वारा समय सारणी निर्धारित की जाएगी। गौठान प्रबंधन समिति द्वारा पशुपालकों से गौमूत्र का क्रय दर निर्धारण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। न्यूनतम राशि 4 रुपए लीटर ;परिवहन व्यय सहित शासन द्वारा प्रस्तावित है। पशुपालक गौमूत्र का विक्रय स्वैच्छिक कर सकेंगे। गौमूत्र का क्रय लीटर के गुणांक में किया जाएगा। जिससे राशि भुगतान में कठिनाई न हो। क्रय किए गए गौमूत्र की राशि का भुगतान गौठान प्रबंधन समिति द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में हितग्राहियों को किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जिले की गौठानों में 15352 मवेशी पंजीकृत हैं। बिरकोनी में 157 पशुपालक परिवार हैं। इसमें साईं स्व सहायता समूह गौठानों में विभिन्न गतिविधियां संचालित करती है। वहीं गोड़बहाल में 77 पशुपालक है। यहां नारी शक्ति स्व सहायता समूह सक्रिय है। गौठानों में गौमूत्र गौठान समिति के जरिए खरीदा जाएगा।

आंगनबाड़ी में लगी चौपाल,टीबी रोग के प्रति किया जागरूक

जोहार छत्तीसगढ़-रायपुर।

तिल्दा विकासखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी चैंपियंस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल आयोजित किये जा रहे है। यह चौपाल आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायत के सामुदायिक केंद्रों एवं विद्यालयों में आयोजित करवाए जा रहे हैं। और लोगों में टीबी रोग के प्रति फैली अज्ञानता को दूर करने में लाभदायक साबित हो रहे है। जागरूकता चौपाल का उद्देश्य लोगों में समय रहते टीबी की पहचान कर संक्रमित व्यक्ति को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में आई विमला देवांगन कहती है। ष्टीबी रोग के प्रति पूर्व में जो हमारी धारणा थी। वह यहां आकर दूर हुई, विशेष रुप जैसे टीबी संक्रमित रोगी के मरने के बाद ही खत्म होता है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में लगी चौपाल में आकर यह

जानकारी मिली कि टीबी का इलाज नियमित रूप से करने पर इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। व्यक्ति पहले की तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है। टीबी चैंपियन चमेली देवांगन ने चौपाल में आकर टीबी रोग के लक्षण एवं कारणों के बारे में बताया। उन्होंने केंद्र पर मौजूद लोगों को बताया व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी का होना या खांसी के साथ बलगम आना कभी-कभी थूक में खून आना या वजन का कम होनाए भूख न लगना और सांस लेते हुए सीने में दर्द की शिकायत होना क्षय रोग के लक्षण होते है। ऐसा होने पर तुरंत नजदीक के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है।

ृसमय पर पहचान हो जाने से टीबी का इलाज काफी आसान हो जाता है। अगर आपके आस पास किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण दिखते है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाए या मितानिन से संपर्क करें ताकि समय पर संक्रमित के इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। चमेली देवांगन ने बताया । विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक तिल्दा ममता सुनानी के अनुसार विकासखंड में अप्रैल 2022 से चौपाल लगाकर टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों के बीच जाकर स्वास्थ्य विभाग और टीबी चैंपियंस के द्वारा चौपाल लगाई जाती है जिसमें टीबी के बारे में बताया जाता है। अप्रैल से अब तक 13 चौपाल लगाई गई है। प्रत्येक चौपाल में 10 से 15 लोग रहते हैं। इन चौपाल के माध्यम से 17 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने टीबी चैंपियन या मितानिन के सहयोग से अपनी जांच करवाई, उसमें एक संक्रमित पाया गया था जिसका नियमित रूप से इलाज चल रहा। भारत से क्षय रोग को 2025 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को 2023 तक टीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में युद्ध स्तर पर टीबी नियंत्रण की दिशा में कार्य किये जा रहे है।

अच्छी वर्षा होने से धान रोपाई का कार्य शुरू

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

अच्छी वर्षा किसानों के किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून आने के बाद जिले में खरीफ की बुवाई भी हो चुकी है और धान के साथ अन्य फसल भी खेतों में देखी जाने लगी है अच्छी वर्षा होने से किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है कृषि विभाग द्वारा अब तक 68.016 से किसानों को खेती किसानी के लिए 299 लाख का ऋण वितरण किया गया वर्ष 20 21, 22 खरीफ वर्ष में 54.082 किसानों को खेती किसानी के लिए 220 .93 करोड़

का ऋण वितरण किया गया था सहायक संचालक कृषि अमित मोहंती ने हमारे प्रतिनिधि प्रमोद दुबे को बताया कि किसानों ने खरीफ वर्ष 20 22 23 ने लगभग 50: से ज्यादा बोनी पूरी कर ली है। किसान धान रोपा में व्यस्त हो गए हैं। तरह तरफ खेतों में महिलाएं रोपा लगाती हुई देखी जा रही है कृषि विभाग द्वारा जिले में लगभग 264.200 1000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बोनी का लक्ष्य है। जो पिछले खरीफ वर्ष से ज्यादा है इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 95 हजार 110 सेक्टर में किसानों द्वारा खरीफ मौसम की धान, मक्का, दलहन एऔर तिलहन फसलों की बुवाई पुरी की जा चुकी है। पिछले साल इस अवधि में बोनी का प्रतिशत इसी के आसपास था। जिले में चालू मानसून के दौरान विगत 1 जून से 18 जुलाई तक 46, 5 मिलीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है इस दौरान सबसे ज्यादा 71.3 मिली मीटर बारिश महासमुंद विकासखंड में हुई है। किसानों द्वारा धान रोपाई का काम किया जा रहा है।

कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के प्रभार में किया संशोधन

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टरध्डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में सौंपे गए प्रभार में संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य विभाजन कर प्रभार सौंपा गया है। इनमें संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा को विभिन्न शाखाओं के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन आहरण एवं संवितरण सहित। कलेक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तु की जाएगी। जिले के सभी अनुविभाग के लिए राजस्व कार्यों हेतु समन्वय एवं नियंत्रण अधिकारी, जिला विभागीय जांच अधिकारी, भू-अर्जन-भू-बंटन अभियोजन शाखा, ई-प्रशासन अंतर्गत सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन, ई-डिस्ट्रीक्ट् लोक सेवा केन्द्र नाजरात शाखा आहरण संवितरण सहित अभिलेखागार हिंदी, अंग्रेजी, सहित मेडिकल कॉलेज महासमुन्द के संबंध में समस्त कार्य, जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग आदिवासी विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नि:शक्त कल्याण एवं पुनर्वास, जिला नवाचार निधि योजना, परिवहन विभाग, जिला पंजीयक, जिला कोषालय, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, लोक निर्माण विभाग एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद द्वारा समय.समय पर सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर एसके टंडन को प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा आहरण संवितरण सहित कलेक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगीद्ध। नजूल शाखा कलेक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तकाबी शाखा अधिक अन्न उपजाओं शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व समान्य राजस्व मोहर्रिर शाखाए प्रतिलिपि शाखा सहित समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

कोटा मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला महामाया मंदिर पहुंच दर्शन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बेजा कब्जा हटाने दिए निर्देश

जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।

कोटा कृषि उपज मंडी के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शुक्ला अपने समिति के सदस्यों के साथ महामाया मंदिर पंहुच दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। महामाया ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए किसानों के हित में कार्य करने का सुझाव दिया।

कोटा कृषि उपज मंडी के अंतर्गत रतनपुर उप मंडी आता है। जिसके परिसर में प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है उक्त परिसर मे कुछ लोगों के द्वारा बेजा कब्जा किया जा रहा था जिसकी जानकारी मिलने मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला मंडी सचिव जायसवाल नगर के प्रमुख लोगों के साथ पहुंचे एवं कब्जा धारियों से अविलम्ब कब्जा छोड़ने का निर्देश दिया साथ ही मंडी परिसर मे बॉउंड्री वाल एवं दुकान निर्माण करने की बात कहीरतनपुर नगर के आसपास सब्जी उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिसके लिए सब्जी मंडी के समुचित विकास एवं सुविधा की मांग सब्जी उत्पादक हारून बेग द्वारा की गई जिसे शीघ्र पूरा कराने का अश्वाशन दिया गया। निरिक्षण के दौरान पूर्व अध्यक्ष आनंद जायसवाल, मंडी सदस्य सुभाष अग्रवाल,नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे,महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णिमा वैष्णव, मदन कहरा,मंडी सदस्य लाला निर्मलकर, मोती पैंकरा, संजू चौहान,किसान कांग्रेस अध्यक्ष शिवदत्त पाण्डेय,दामोदर क्षत्रिय,शिवा पाण्डेय,रामगोपाल कहरा, रफ ीक बेग,सोनू गुप्ता,पुष्पकांत कश्यप,अमर यादव, रमेश सिंह,कुमारी देवी,अभिषेक मिश्रा, आदि उपस्थित थे।

वर्मी खाद विक्रय से टर्नओवर कमाया 93 लाख, समूह की महिलाएं बोली अब बदल गया लोगों का नजरिया

रोजगार का नया अवतार बन गयी है गोधन न्याय योजना, बड़े आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रहा प्रदेश

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

गोधन न्याय योजना पूरे देश में अपने किस्म की अनूठी योजना है। शासन की गोधन न्याय योजना ने गोबर को एक कमोडिटी में तब्दील कर दिया है। आज गोबर बेचा और खरीदा जा रहा है। शासन छत्तीसगढ़ में पशुपालकों से गोबर खरीद रही है। इस गोबर से गौठानों में स्व सहायता समूहों के द्वारा वर्मी खाद बनाई जा रही है। इस वर्मी खाद के विक्रय से समूहों को जो लाभ हो रहा हैं और उससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसी की एक बानगी देखने को मिलती है स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ के साथ। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के शहरी गौठान में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में संलग्न स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ, जो एक महिला स्वसहायता समूह है, आजकल काफी चर्चा में है और इस चर्चा का विषय है कि किस तरह इस समूह ने वर्मी खाद

बेचकर 93 लाख रूपए कमाए हैं। चर्चा हो भी क्यों ना किसने सोचा था कि गोधन इतने काम का हो सकता है। धार्मिक कार्यो में गोबर का बेहद महत्व माना जाता है पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को आर्थिक बदलाव की धुरी बना दिया है। पूरे जिले में सर्वाधिक वर्मी खाद उत्पादन करने वाले विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ की स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ की सदस्य प्रीति टोप्पो बताती हैं कि मैं पहले डोर-टू-डोर कचरा क्लेक्शन का कार्य करती थी। जब गोधन न्याय योजना शुरू हुई तो शहर के गौठान में समूह के रूप में जुड़कर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का कार्य शुरू किया। तब घर परिवार के लोग खुश नहीं थे, लेकिन जैसे.जैसे उत्पादन एवं विक्रय से लाभ मिला, लोगों का हमारे प्रति नजरिया बदलने लगा। इस योजना से हमें स्वरोजगार का जरिया मिला है और ये कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि समाज में हमारा मान.सम्मान बढ़ा है। समूह द्वारा अब तक 9 लाख 30 हजार किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन कर बेचा गया है जिसके एवज में समूह को 93 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। इसमें समूह का शुद्ध लाभ 36.49 लाख रुपए है। प्रीति ने बताया उसे लाभांश से लगभग 50 हजार रुपये मिले हैं। उसने बहन की शादी में कुछ कर्ज लिया था। वो इस पैसे से छूट गया और बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए साईकल लेकर दी है। घर के लोग पहले घर में टाइम ना दे पाने के कारण थोड़ा नाराज थे पर अब आय देखकर खुश हैं।

आत्म र्निभरता का मिला रास्ता

इस समूह में 73 महिलाएं हैं। यानि सीधे.सीधे 73 महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। गौठान में वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन के काम से जुड़ी कोई महिला निर्धन परिवार से है तो किसी ने कभी घर से बाहर निकलकर कभी काम नहीं किया। इस काम से हुई कमाई ने उन्हें अपने परिवार का मजबूत स्तंभ बनाया है। उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है।

लिटिया ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव पर लाखों रुपए के गबन का आरोप

जिला कलेक्टर के जनदर्शन में हुई थी शिकायत

जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।

जनपद पंचायत के अंर्तगत आने वाले लिटिया ग्राम पंचायत की सरपंच-सचिव पर 15 लाख से ऊपर का गबन भ्रष्टाचार की शिकायत पंचायत के उपसरपंच.पंच सहित ग्रामीणों के द्वारा 28-जून-2022 को जिला कलेक्टर के जनदर्शन में किया गया था।

सरपंच पति के हस्तक्षेप से उपसरपंच पंच सहित ग्रामीणों में आक्रोश,शिकायत करने पर गाली-गलौज दुर्व्यवहार छेड़खानी के झूठे मामले में पंसाने की देता है धमकी

उपसरपंच.ग्राम पंचायत लिटिया के द्वारा अपने शिकायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय में हितग्राहियों को मिलने वाले अंशदान की राशि 9.96000 मूलभूत योजना 2021-22 के तहत बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव के 4.1624/ सामुदायिक भवन की मरम्मत पर 95.000 गली.मरम्मत 2.13000 जिला.विकास निधि के तहत मोहंदी में सीसी.रोड़ निर्माण 180.000 15-वित्त.मद से विकास कार्यो हेतु लाखों रुपए की विभिन्न किश्तों को पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा बिना कार्य के फर्जी बिल प्रस्तुत कर गबन के आरोप सहित पीएफ एमएस मद से 2.20.000 हैंडपंप मरम्मत प्राथमिक शाला मोहंदी मरम्मत के कार्य मे भी गबन के आरोप ग्राम पंचायत के उपसरपंच.पंच सहित ग्रामीणों ने10 बिंदुओं पर लिखित शिकायत के रूप में कई गई थी।

जिले से तीन सदस्यीय जांच टीम पहुंची लिटिया ग्राम पंचायत मचा हड़कंप

पंचायत सरपंच सचिव पर लाखों रुपए के गबन व भ्रष्टाचार की जिला-कलेक्टर के जनदर्शन में शिकायत के बाद जिला कलेक्टर के आदेश के बाद 15-जुलाई को तीन.सदस्यीय जांच टीम लिटिया ग्राम.पंचायत जांच में पहुंची। जांच टीम की ग्राम पंचायत की सरपंच उपसरपंच.पंच सचिव सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में जिले से पहुची जांच टीम ने संबंधित दस्तावेज-अभिलेख का किया परीक्षण शुरू किया गया। जांच टीम के समक्ष सरपंच की उपस्थिति में काफ ी गहमागहमी.हुई आरोप.प्रत्यारोप हुए शुरुआती जांच के दौरान पंचायत के उपसरपंच पंच पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों के बयान जांच टीम के द्वारा लिया गया लगभग सभी ने वर्तमान सरपंच पर लाखों रुपये के गड़बड़ी का आरोप लगाया कुछ देर के बाद मीडिया की उपस्थिति में जांच टीम के मौके का निरीक्षण किया गया।

जहा पर जांच टीम के द्वारा शिकायत में कही बातें लगभग अधिकतर सही पाई गई। ग्राम.पंचायत के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए कराई गई शासकीय.बोर सरपंच के अपने निजी जमीन उसके स्वयं के घर के अंदर पाया गयाण्उसके अलावा अधिकांश शिकायतें जो की गई थी लगभग सभी शिकायतें जांच टीम को सही मिलीण्जांच टीम के द्वारा जांच के दौरान सरपंच-सरपंच पति के साथ कई बार उपसरपंच पंच सहित ग्रामीणों के साथ वाद.विवाद की स्थिति भी निर्मित हुईण्गाली.गलौज व गहमागहमी की स्थिति के बीच जांच टीम वापस ग्राम पंचायत लिटिया पहुंच गई। जहा से मीडिया से बात करने के दौरान जांच टीम के अशोक धिरहि ने बताया कि मौके पर जाकर जांच टीम के द्वारा भु-अभिलेखो का परीक्षण संबंधित दस्तावेज के अवलोकनध्पश्चात अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को सौंपेगी। प्रथम दृष्टया जांच टीम ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकारी।

जांच टीम के ग्राम-पंचायत पहुंचने से पहले ही पंचायत के बाहर राशन कार्ड सहित दस्तावेज जले मिले

जांच टीम के ग्राम पंचायत लिटिया में आने से पहले पंचायत भवन के बाहर ही कुछ पुराने राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जले हुए मिले मीडिया की नजर पड़ने के बाद जांच टीम को इसके बारे में अवगत कराया गया जिसके बाद जांच टीम के एक अधिकारी ने जले हुए राशन कार्ड और दस्तावेजों का अवलोकन किया। और इसे भी अपनी जांच में शामिल किया कुछ देर के बाद पूर्व सरपंच सहित जनपद सदस्य सहित अन्य ग्रामीण भी जल हुए राशन कार्ड सहित दस्तावेजो को खंगालने हुए सवाल उठाने लगे। जांच टीम ने इसे भी अपनी जांच में शामिल किया गया है। देखना होगा की जांच टीम के द्वारा जिला कलेक्टर को क्या रिपोर्ट सौंपती है।

जांच के दौरान जांच टीम के अधिकारी सरपंच पति को ही सरपंच कहकर संबोधित करते रहे

मौके के निरीक्षण के दौरान जांच टीम के अधिकारियों के द्वारा सरपंच पति को वो सरपंच कहकर संबोधित करते रहे। इस दौरान जांच टीम के आगे पीछे मौके के निरीक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेख दस्तावेज के अवलोकन के दौरान सरपंच पति की उपस्थिति लगातार बनी रही। जांच टीम के निरीक्षण के दौरान लिटिया सरपंच की अनुपस्थिति में सरपंच पति की उपस्थिति का उपसरपंच पंचों ने विरोध किया। मीडिया ने भी जांच टीम को पंचायत सरपंच की अनुपस्थिति में जांच को अवैधानिक बताया। जिसके बाद त्वरित रूप से जांच टीम ने पंचायत सरपंच दुलेश्वरी नेताम को उपस्थित होने को कहाण्सरपंच की उपस्थित होने के बाद जांच टीम ने जांच आगे बढ़ाई। बीच में ऐसे कई मौके आय जहा पर सरपंच/पति के साथ उपसरपंच-पंचों व ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति बनती दिखाई दी।

एक नजर

किसानों को नहीं मिल रहा खाद, बाजार में चल रही कालाबाजारी

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

खाद की कालाबाजारी भारी मात्रा में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की घोषणा कर रही है। इधर के लिए किसान को खाद नहीं मिल रहा है। यूरिया का सास की दर 267 रुपए वही डीएपी का 1300 रुपए है। लेकिन यह किसान को सोसाइटी से नहीं मिल रहा है। महासमुंद क्षेत्र के किसान परेशान है। और व्यापारी से अधिक दाम मे खाद लेने विवश है। आसपास ग्रामीणों सभी सरकारी समितियां में खाद कमी है। जिसके कारण किसानों को उचित दाम में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है ।वहीं प्राइवेट किसी केंद्रों में खाद्य का भंडारण है। जिससे किसानों को खाद कृषि केंद्रों में जाकर व्यापारियों से लेना पड़ रहा है। किस विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए खा देखने वाले व्यापारी बेखौफ होकर खुलेआम 400 500 से अधिक दामों में बेच रहे हैं यूरिया 265 रुपए है वहीं डीएपी 1300 रुपए है उसे 1600 रुपए से 1700 रुपए तक बेचा जा रहा है।

चाइल्डलाइन की टीम ने जंजीर से बंधी 15 वर्षीय नाबालिग को मैनपाट के रास्ते से रेस्क्यू कर भेजा चाइल्ड लाइन

जोहार छत्तीसगढ़-सीतापुर।

चाइल्डलाइन की टीम कल क्षेत्र भ्रमण पर निकली थी। जहां मैनपाट के रास्ते पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 15 वर्षीय नाबालिग लड़की, उनको मिली उस लड़की के हाथ और पैर पर जंजीर बंधा हुआ था। चाइल्डलाइन की टीम द्वारा तत्काल 112 की मदद से लड़की को रेस्क्यू कर सीतापुर थाना लाया गया तथा लड़की का कोविड जांच कराने के बाद, चाइल्ड लाइन सीतापुर की टीम द्वारा उसे चाइल्डलाइन केयर अंबिकापुर भेज दिया गया है,वहीं जब बलजीत राम कुजूर चाइल्डलाइन टीम मेंबर सीतापुर, से लड़की के बारे में जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि वह नाबालिग लड़की अपना नाम उर्मिला बता रही है तथा निवास की जानकारी लेने पर खुड़ियारानी और सरहापानी का निवासी होना बताया है। वह अपने माता-पिता व परिजन का नाम नहीं बता पा रही है। साथ ही वह इस क्षेत्र में कैसे पहुंची उसके बारे में भी उसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हत्या को छुपाने के नियत से आरोपी का सहयोग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

उत्तरा कुमार चौहान पिता रामबिलास चौहान उम्र 48 साल साकिन बहेरघट थाना व जिला बेमेतरा थाना हाजिर आकर जुबानी बताकर मर्ग इन्टीवेशन दर्ज कराया कि 26 जून 2022 के सुबह गांव के चोवाराम निषाद एवं गांव के रमेश्वर निषाद लोगो ने बताया कि गांव के डोम सिंह निषाद ने अपने बेटा शोभनाथ उम्र 02 साल 06 माह साकिन बहेरघट थाना व जिला बेमेतरा को 24 जून 2022 के दोपहर करीबन 02,30 बजे ग्राम बहेरघट कन्हार खार थुकेल साहू के धनहा खेत में ले जाकर शोभनाथ निषाद को जमीन में पटककर पैर लात से गला को दबाकर शोभनाथ का हत्या करने पर मृतक शोभनाथ के शव को घटना स्थल से चोवाराम निषाद घर लाकर लोगो को मृतक को बिमारी से मृत्यु होना बताकर मृतक के शव को जला दिये है कि रिर्पोट पर मर्ग क्रमांक 82/222 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच पर से अपराध सदर धारा 302, 201, 120 बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह ने आरोपियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। जिसके तहत अतिण् पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया एवं थाना स्टाफ को अपराध विवेचना हेतु लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी डोमसिंह ऊर्फ पकलू निषाद 34 साल साकिन बहेरघट थाना व जिला बेमेतरा से पुछताछ करने पर बताया कि अपने लडका शोभनाथ निषाद उम्र 02 साल 06 माह को अपने तरफ का बच्चा नहीं है कि शंका कर गुस्से में आकर जमीन में पटककर हाथ मुक्का से मारपीट कर पैर के पंजा से गला व सीना को दबाकर हत्या करना स्वीकार किये आरोपी को 15 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी चोवाराम एवं कमल निषाद, रमेशर निषाद से पुछताछ करने पर घटना दिनांक को डोम सिंह निषाद द्वारा मृतक शोभनाथ निषाद का हत्या करने के बाद हत्या को छुपाने के नियत से एक राय होकर आपसी सहमति से मृतक के शव को गांव के शमशान घाट में ले जाकर शव को आग से जला देना स्वीकार किये है।

कोंटा नगर पंचायत में सर्वे कार्य प्रारंभ, बाढ़ से हुई क्षति का किया जाएगा सर्वेक्षण

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

बाढ़ से हुई क्षति के आंकलन के लिए कोंटा नगर के समस्त वार्ड में आज से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। कलेक्टर हरिस एस द्वारा राजस्व अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त करते हुए समस्त वार्ड पटवारी, सचिवों को सर्वे के लिए नियुक्त किया गया गया। वार्ड पार्षदों के सहयोग से संयुक्त टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को हुई संपत्ति क्षति,, घरेलू सामान क्षति, पशु क्षति एवं अन्य क्षति का सर्वेक्षण कर क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रकरण तैयार किए जाएंगे।

आवश्यकता है

		पद
1. समाचार रिपोर्टर	-	3
2. कम्प्यूटर आपरेटर	-	1
3. ऑफिस कार्य के लिए	-	3

वेतन योग्यतानुसार

इच्छुक युवक/युवति अपना बायोडाटा के साथ संपर्क करें।

दैनिक जोहार छत्तीसगढ़

कार्यालय धरमजयगढ़

मो, 9479177711, 7489419194 ,7879121221

कोरोना से उठा पिता का साया तो मिला अनुकम्पा नियुक्ति का सहारा

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

राज्य सरकार द्वारा मानवीय सहानुभूति को ध्यान मे रखते हुए बीते वर्ष अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत के सीमा बन्धन को समाप्त कर दिये जाने से प्रदेश के दिवंगत शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के स्वजनों को अनुकम्पा नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी बेमेतरा में कार्यरत लगभग 47 वर्षीय स्व. मदन लाल ठाकुर का 18 अप्रैल 2021 को कोरोना महामारी की दूसरी लहर में असमय मौत हो गई। नियति को कौन टाल सकता है। ऐसे समय में उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई। परिवार मे पत्नी के अलावा दो पुत्री है। ग्राम अरसनारा तहसील पाटन जिला दुर्ग में उनका संयुक्त परिवार है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी मदन ठाकुर की 23 वर्षीय बड़ी पुत्री कुमारी शुभि ठाकुर स्नातक तक पढ़ी लिखी है। संकट के इस मुश्किल घड़ी में पिता के निधन के दो माह के पश्चात उन्हे जिला कार्यालय उपायुक्त आबकारी रायपुर में सहायक ग्रेड-03 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति मिली। शुभि ने 17 जून 2021 को अनुकम्पा नियुक्ति के तहत पदभार ग्रहण की। शुभि ने कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि अनुकम्पा नियुक्ति के अनेक लंबित प्रकरणों के बीच उनको नौकरी इतनी जल्दी मिल पाएगी। प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही यह सम्भव हो पाया और आज वह अपने परिवार के लिए कुछ करने लायक सक्षम हो पाई। राज्य शासन के इस राहत भरे फैसले पर शुभि ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। शुभि ने कहा कि पिता के न होने से परिवार का अधूरापन यद्यपि कभी खत्म नहीं होगाए लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की। प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही यह सम्भव हो पाया और आज वह अपने परिवार के लिए कुछ करने लायक सक्षम हो पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया।

कलेक्टर हरिस एस ने कोंटा आत्मानंद राहत केंद्र में लोगों से की मुलाकात

अधिक जनसंख्या वाले वार्ड में दो दल के माध्यम से सर्वे कार्य करने के दिए निर्देश

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

सुकमा कलेक्टर हरिस.एस ने बुधवार को कोंटा में स्वामी आत्मानंद स्कूल में राहत केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों से चर्चा की और भोजन सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान वार्ड क्रमांक 07 के निवासी शेख मुनीर ने बताया की राहत केंद्र में प्रशासन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाएं गुणवत्ता पूर्ण है। समय पर गरम भोजन, सूखा राशन प्रदाय किया जाता है। टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। राहत केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरदानी वितरित की गई है। और मेडिकल कैंप के माध्यम से उपचार कर दवा वितरण किया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल में बन रहे नए भवन में शरण लिए एक अन्य परिवार ने बताया कि विद्युत व्यवस्था की कमी है। जिसपर कलेक्टर हरिस एस ने एसडीएम कोंटा एवं संबंधित अधिकारी को राहत केंद्र में शीघ्र बिजली व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। उन्होंने लोगों से कुशलक्षेम जाना और कहा की रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में अधिकारियों, पत्रकारों के साथ किया भोजन

कलेक्टर हरिस एस एवं एसपी सुनील शर्मा ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में राहत केंद्र के लिए बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी जांची। उन्होंने रसोई स्थल का अवलोकन किया, और इसके पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों सहित गणमान्य पत्रकारों के साथ भोजन किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ डीएन कश्यप, एसडीएम कोंटा बनसिंह नेताम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे, एसडीओपी कोंटा गिरजा शंकर ने भी भोजन ग्रहण किया। पत्रकारों में सतीश चांडक, शिव यादव, रफीक खान, वरुण नायडू एवं नवीन गोंदी उपस्थित रहे। सभी ने राहत केंदों में प्रदाय किए जा रहे भोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की।

प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर करे क्षति का आंकलन-कलेक्टर

कोंटा नगर पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों में आज से बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। कलेक्टर एवं एसपी ने वार्ड क्रमांक 6 में सर्वे कार्य का अवलोकन किया। लोगों ने बताया की सर्वे कार्य के प्रति संतुष्टि जाहिर की। कलेक्टर ने सर्वे कार्य में लगे अधिकारियों को वार्ड के समस्त परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बाढ़ से हुई वास्तविक क्षति का आंकलन कर प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए है। साथ ही जिन वार्ड में परिवार संख्या अधिक है। वहां दो टीम बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने कोंटा सहित सुकमा तहसील के पटवारियों को सर्वे कार्य में लगाने के निर्देश दिए। ताकि सर्वे काय जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नगर पंचायत के सभी वार्डों में साफ-सफ ाई कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, हैंडपंप, बोरवेल आदि जल स्त्रोतों का क्लोरिनेशन करने, मच्छरदानी वितरण नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को राहत केंद्र में शरण लिए लोगों सहित, वार्ड में घर घर जाकर मौसमी बीमारियों की जांच कर दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

कुशलक्षेम जाना, व्यवस्थाओं का लिया संज्ञान

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक नारायण बाईन, द्वारा आसमा पब्लिसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित कर मेडरमार कालोनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक -**नारायण बाईन,** फोन -फैक्स 07766299001, मो, 9479177711, 7489419194 Email-joharchhattisgarh@gmail.com, joharchhattisgarh@yahoo.co.in